वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी.आर. मजीठिया से पहले, जे.

भारत संघ,-अपीलकर्ता।

बनाम

गुरकिरपाल सिंह, प्रतिवादी।

1989 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 186

4 अक्टूबर 1989.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 16—समान अवसर–का अर्थ–उसे अवसर पर विचार करना–नियुक्ति के प्रस्ताव का कोई अधिकार नहीं।

माना गया कि संविधान के तहत जिस समानता की गारंटी दी गई है वह किसी पद के लिए आवेदन करने और योग्यता के आधार पर उस पर विचार करने का अवसर है। यह अधिकार वास्तव में नियुक्त किये जाने तक सीमित नहीं है। प्रत्याशित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के प्रयोजनों के लिए चयन और चयन की प्रक्रिया उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं बनाती है जिसे एक परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है। कानूनी अधिकार के बिना कोई भी परमादेश नहीं मांग सकता।

(पैरा 5)

आयोजित। कि वर्तमान मामला प्रारंभिक नियुक्ति का मामला है। जिस व्यक्ति का चयन कर लिया गया है उसे नियुक्ति के प्रस्ताव का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। (पैरा 8)

उपरोक्त उल्लिखित सिविल रिट याचिका में माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निफियोत्री के दिनांक 15 दिसंबर, 1988 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के खंड एक्स के तहत लेटर पेटेंट अपील।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि 15 दिसंबर, 1988 के माननीय एकल न्यायाधीश के आक्षेपित फैसले की कार्रवाई को अपील के फैसले तक रोक दिया जाए।

एच. एस. बराड़, भारत सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील।

प्रतिवादी की ओर से पी.एस. पटवालिया, अधिवक्ता।

प्रलय

जी. आर. मजीठिया, जे.

(1) क्या कोई व्यक्ति जिसे प्रत्याशित रिक्तियों के लिए चुना गया है, उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त करता है जिसे परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है, यह मुख्य प्रश्न है जो फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील में निर्धारण के लिए उठता है। विद्वान एकल न्यायाधीश वी, ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति की पेशकश करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया।

(2) तथ्य: 1985 में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और लीडो तिब्बती सीमा पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के 45 पद विज्ञापित किए गए थे। इसके जवाब में प्रतिवादी (बाद में याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) ने भी आवेदन किया और 9 अप्रैल 1986 को लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार आदि दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (संक्षिप्त सी.आर.पी.एफ. के लिए) में पुलिस उपाधीक्षक समूह 'ए.एल.' पद पर नियुक्ति के लिए 14 व्यक्तियों की एक चयन सूची तैयार की गई थी और याचिकाकर्ता का नाम सूची में क्रम संख्या 11 पर था। चयनित उम्मीदवारों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जानी आवश्यक थी। याचिकाकर्ता की चिकित्सीय जांच की गई और 2 मई 1986 को उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया गया और उसे तदनुसार सूचित किया गया। 12 जून

1986 को, महानिदेशक सी.आर.पी.एफ. ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यद्यपि उसका नाम सी.आर.पी.एफ. में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल था, क्या वह उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस में पुलिस, और यदि हां, तो उसे सी.आर.पी.एफ. के लिए अपनी लिखित प्राथमिकता भेजनी चाहिए। इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने सी.आर.पी.एफ. के लिए अपनी प्राथमिकता बताई। चयन सूची में से क्रम संख्या 12, 13 और 14 पर उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता, जिसका नाम चयन सूची के क्रम संख्या 11 पर था, को अपेक्षित प्रस्ताव नहीं मिला। पूछताछ करने पर, महानिदेशक, सी.आर.पी.एफ. ने 9 नवंबर, 1986 को याचिकाकर्ता को सूचित किया कि "आपको बल में नियुक्ति का कोई प्रस्ताव देना संभव नहीं है।" अपीलकर्ताओं के इस निर्णय को महानिदेशक, सीआरपीएफ के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, जिसे रिट याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता का चयन होने के बाद, मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी फिटनेस की घोषणा की गई और उसके चरित्र के सत्यापन की मंजूरी दी गई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर द्वारा पूर्ववृत्त के अनुसार, उन्हें नियुक्ति से इंकार करना अपीलकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से मनमाना था। बिना किसी कारण का खुलासा किए गुप्त जानकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ठेस पहुंचाई क्योंकि याचिकाकर्ता को उपरोक्त निर्णय लेने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(3) उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था। जहां तक याचिकाकर्ता के चयन का सवाल है, तथ्यात्मक स्थिति स्वीकार कर ली गई है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देने का निर्णय इस आधार पर उचित था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर प्रकृति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। रिपोर्टों में कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद से वह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और चरमपंथियों के साथ जुड़े हुए थे और याचिकाकर्ता को सी.आर.पी.एफ. में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त करना खतरनाक था।

जिसे कानून-व्यवस्था के रखरखाव और सुरक्षा कर्तव्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को एकमात्र आधार पर अनुमति दी कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति से इनकार करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं था और ठोस और ठोस सामग्री का खुलासा नहीं किया गया था जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि याचिकाकर्ता बल में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं था। .

(5) संविधान के तहत जिस समानता की गारंटी दी गई है वह किसी पद के लिए आवेदन करने और योग्यता के आधार पर उस पर विचार करने का अवसर है। यह अधिकार वास्तव में नियुक्त होने तक विस्तारित नहीं है। प्रत्याशित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के उद्देश्य से चयन और चयन की प्रक्रिया उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं बनाती है जिसे एक परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है। कानूनी अधिकार के बिना कोई भी परमादेश नहीं मांग सकता। मणि सुब्रत जैन आदि आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [1] का संदर्भ लेना उपयोगी होगा, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने परमादेश का दायरा बताया था। इस मामले में, प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उठा: उच्च न्यायालय ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में बार से सीधी भर्ती के कोटे में दो रिक्तियों को भरने के लिए बार के योग्य सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए। उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को जिला/अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में दो अपीलकर्ताओं के नामों की सिफारिश की। हरियाणा सरकार ने सिफारिश खारिज कर दी. इसके बाद, दोनों अपीलकर्ताओं ने अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और जिला/अतिरिक्त जिला

---

[1] ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 276

और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एक परमादेश मांगा। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी और मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया, जहां यह कहा गया: -

“अनुच्छेद 23डी के तहत जिला न्यायाधीशों की प्रारंभिक नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करता है। यदि उच्च न्यायालय द्वारा नामों की सिफारिश की जाती है, तो राज्यपाल के लिए सिफारिश स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

और इन परिसरों में, शीर्ष न्यायालय ने परमादेश की रिट जारी करने से इनकार कर दिया और निम्नानुसार कहा: -

“यह प्राथमिक है, हालांकि यह दोहराया जाना चाहिए कि कोई भी कानूनी अधिकार के बिना परमादेश नहीं मांग सकता है। कानूनी शिकायत से पीड़ित व्यक्ति परमादेश मांगने से पहले कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल तभी व्यथित कहा जा सकता है जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिसका कुछ करने का कानूनी कर्तव्य है या कुछ करने से बचना है (देखें हैल्सबरी लॉज़ ऑफ इंग्लैंड का चौथा संस्करण, खंड 1, पैराग्राफ 122); हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर, (1974) 1 एससीआर 165 = (ए.आई.आर. 1973 एससी 2216); जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार हाजी बशीर अनमेद (1976) 3 एससीआर 58=ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 578 और फैरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज़ पैराग्राफ 198।"

केरल राज्य बनाम ए. लक्ष्णितकु प्रथम और अन्य [2] में शीर्ष न्यायालय के हालिया फैसले में इस फैसले का फिर से पालन किया गया, और यह निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ: केरल के उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को भेजा केरल राज्य बार से जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा 14 नामों का दंड तय किया गया है। यह कहा गया था कि नियुक्तियाँ नियम 14 (सी), केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 1958 में निर्धारित पदों के आरक्षण को नियंत्रित करने वाले रोटेशन के चक्र के अनुसार की जानी थीं, जैसा कि नियम 2 (बी) केरल राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1961 के अनुसार आवश्यक है। .

तदनुसार, नियुक्तियाँ 'लैटिन-कैथोलिक और एंग्लो-इंडियन' समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पहली रिक्ति के साथ शुरू होनी थीं, जो रोटेशन के चक्र में 8वीं बारी थी।

चूंकि रोटेशन के चक्र में 8वीं, 10वीं और 12वीं में 'लैटिन-कैथोलिक और एंग्लो-इंडियन' 'अन्य पिछड़ा वर्ग' और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' से संबंधित कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए पहली रिक्ति को भरना पड़ा। नियमों के नियम 15 (ए) के कारण पारित समुदाय या समूह के ठीक बगल वाले समुदाय या समुदायों के समूह से संबंधित एक उपयुक्त उम्मीदवार द्वारा, यानी, प्रतिवादी 1 श्रीमती ए. लक्ष्मीकुट्टी द्वारा 'एझावा' समुदाय का सदस्य , योग्यता के क्रम में 6वें स्थान पर, रोटेशन के चक्र में 'एझावा, थियास और बिलावास' समूह में 14वें स्थान पर आते हैं। दूसरी रिक्ति, यानी, रोटेशन के चक्र में 9वीं, प्रतिवादी 3, कृष्णन नायर, योग्यता के क्रम में प्रथम, द्वारा खुली प्रतियोगिता द्वारा भरी जानी थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा नहीं मानी. जिन उम्मीदवारों के नाम जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। रिट याचिका की अनुमति दी गई थी। अपील पर, केरल उच्च न्यायालय

2

के फैसले को उलट दिया गया। मणि सुब्रत जैन के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार को दोहराते हुए, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

“अधिकार का अस्तित्व परमादेश रिट जारी करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की नींव है। न्यायिक राय की वर्तमान प्रवृत्ति यह प्रतीत होती है कि किसी पद पर चयन न होने की स्थिति में परमादेश का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि हम निर्णय को तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ना चाहते।"

इस मामले को हमने एल.पी.ए. में भी निपटाया था। 1988 की संख्या 434 (हरियाणा राज्य बनाम सत्य प्रकाश आदि), 10 मार्च 1989 को निर्णय लिया गया। उस मामले में यह देखा गया कि लोक सेवा आयोग को नियुक्ति के मामले में मनमानी और भाई-भतीजावाद से बचने के लिए किसी पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करना है। . चयन आयोग द्वारा किया जाना है और सरकार को लोक सेवा आयोग द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की सूची में योग्यता के क्रम के अनुसार आयोग द्वारा चयनित और अनुशंसित लोगों को नियुक्त करके पदों को भरना है। आयोग को केवल सिफारिशें करने की आवश्यकता है और नियुक्ति के लिए अंतिम प्राधिकारी सरकार है। सरकार सिफ़ारिश को स्वीकार कर सकती है या इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है। उस निष्कर्ष पर पहुंचने में, शीर्ष न्यायालय के दो निर्णयों का संदर्भ दिया गया- हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य [3], और जतिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [4]।

(6) एकल न्यायाधीश ने सीखा कि सीआरपीएफ के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव का कानूनी अधिकार कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

---

[3] 1973 (2) .एस.एल.आर. 137 |

[4] ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1850।

(7) तब प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया: पी. नलिनी और अन्य -v. मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम [5], और मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमाशंकर रघुवंशी और अन्य [6]। पी. नलिनी के मामले (सुप्रा) में, विद्वान न्यायाधीशों ने सुभाष चंदर का उल्लेख करने के बाद

मारवाह का मामला (सुप्रा) इस प्रकार देखा गया: -

"सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोर दिए गए सिद्धांत ने प्रासंगिक कानूनी स्थिति पर प्रकाश डाला है जो इस मामले को नियंत्रित करना है। जहां तक आदेश प्रदर्शनी पी-8 की वैधता का सवाल है, तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में उक्त सिद्धांत के आवेदन से मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में समाप्त होना चाहिए।"

विद्वान न्यायाधीशों ने उस विशेष मामले के स्पष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता को राहत दी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सुभाष चंदर मारवाह के मामले (सुप्रा) में फैसले का पालन किया, जहां यह माना गया था कि रिक्ति के अस्तित्व से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

रमाशंकर रघुवंशी के मामले (सुप्रा) में, शीर्ष न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील को सीमित लेकिन गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया। ओ. चिन्नप्पा रेड्डी जे. ने इस प्रकार कहा: -

"भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ और यूनियन बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानूनों की समान सुरक्षा, अवसर की समानता का अधिकार राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामले में मौलिक अधिकार घोषित किए गए हैं। फिर भी

---

[5] 1978 (1) एस.एल.आर. 623|

[6] 1983 (1) एस.एल.आर. 575|

मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवादी को इस आधार पर रोजगार देने से इनकार करना चाहती है कि एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वह किसी राजनीतिक संगठन से संबंधित था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई कुछ सेवा आचरण नियमों के विपरीत, सरकार की सेवा में प्रवेश करने के बाद राजनीतिक गतिविधि में उनकी वर्तमान भागीदारी के आधार पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी ने कभी भी किसी अवैध, शातिर या विध्वंसक गतिविधि में भाग लिया है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रतिवादी हिंसक कृत्यों का अपराधी था या है, या उसने किसी को हिंसक कृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसमें हिंसा या बुराई को जोड़ने या हिंसा, बुराई या अन्य अपराध से जुड़ी किसी घटना का कोई संदर्भ नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले, उन्होंने कुछ 'आरएसएस या जनसंघ गतिविधियों' में भाग लिया था। वे गतिविधियाँ क्या थीं इसका कभी खुलासा नहीं किया गया। न तो आरएसएलएस और न ही जनसंघ पर किसी विध्वंसक या अन्य अवैध गतिविधि में शामिल होने का आरोप है; न ही संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।"

(8) राजनीतिक विरोधी गतिविधि और राष्ट्र विरोधी गतिविधि के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक सरकारी कर्मचारी सेवा में प्रवेश करने के बाद स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर सकता है। यह सरकारी सेवा आचरण नियमों के विपरीत हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधि नियुक्ति देने से इनकार करने का वैध आधार होगी। इसके अलावा, सेवा समाप्ति से संबंधित उस मामले में निर्णय पुलिस की रिपोर्ट पर आधारित था कि कर्मचारी सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। वर्तमान मामला प्रारंभिक नियुक्ति का मामला है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिस व्यक्ति का चयन किया गया है उसे नियुक्ति के प्रस्ताव का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रमाशंकर रघुवंशी के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार का इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh